International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 04(II), October - December, 2021, pp.99-104

बैंकिंग एवं असंगठित व्यवसाय क्षेत्र पर कोविड़–19 का प्रभाव

डॉ. जगदीश प्रसाद मीना*

सार

कोरोना वायरस के चलते देश में चल रहे लॉकडाउन की वजह से बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन के चलते नया लोन पूरी तरह से बंद है, वहीं 3 महीने के मोरेटोरियम से कलेक्शन भी जीरो हो गया है। रिटेल और एमएसई सेक्टर पर बड़ा असर पड़ रहा है। पिछले दिनों रीकैलाईजेशन से बैकिंग को लेकर एक आस जगी थी लेकिन लॉकड़ाउन ने उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। लॉकड़ाउन में आरबीआई द्वारा लिक्विडिटी बढ़ाने के उपाय भी पर्याप्त नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में बैंकिंग सेक्टर का प्रदर्शन खराब हो रहा है।

शब्दकोशः *कोरोना वायरस, फाइनेंशियल सेक्टर, लॉकडाउन, एमएसई सेक्टर, आरबीआई।*

प्रस्तावना

निजी बैंकों की बात करे तो लॉकडाउन से पहले तक इसका वित्तीय प्रदर्शन मजबूत था। हेल्दी क्रेड़िट ग्रोथ, नेट इंट्रेरेस्ट मार्जिन के बढ़ने मजबूत कसटमर बेसे का फायदा बैंकों को मिल रहा था लेकिन लॉकडाउन से स्थिति बिगड़ गई कोविड़–19 की वजह से जिस तरह से मंदी का डर बढ़ा है, बैंकिंग सेक्टर पर उसका असर पड़ रहा है, इसका सही असर मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में होगा, लेकिन मार्च तिमाही के लिए बैंक प्रोविजनल बढ़ा सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने देश में फैल रही कोरोना वायरस महामारी के संभावित खतरे को देखते हुए सभी बैंकों और वित्तिय संस्थानों से उनकी बैलेंस सीट, सम्पत्ति गुणवत्ता, तरलता सहित अन्य मामलों मं पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने को कहा है। रिजर्व बैंक ने बैंकों, शहरी सहकारी बैंको, गैर बैकिंग कंपनियाँ, भुगतान और लघु वित्त बैंकों के नाम जारी अधिसूचना में कहा है कि भारत में कई मामलों की पुष्टि हुई है। इस स्थिति को देखते हुए और भारतीय वित्तिय प्रणाली को मजबूत बनाये रखने के लिए समन्वित रणनीति अपनायें जाने की जरूरत है, रिजर्व बैंक ने सभी वित्तिय उधमों से कहा है कि वह अपने ग्राहकों को जहाँ तक सम्भव हो सके डिजिटिल बैंकिग सुविधाओं का इस्तेमाल करने को कहा रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तिय संस्थानो से कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्तिय प्रणाली में गड़बड़ी के परिणामस्वरूप भारत में भी कोविड़–19 के प्रसार और उसके अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर उनके कामकाज सम्पत्तियों की गुणवत्ता और तरलता पर प्रभाव का आकलन करना चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा कि पूरी स्थिति पर व्यावसायिक और सामाजिक परिपेक्ष दोनों तरह से नजदीक से निगाह रखने की जरूरत है और स्थिति को देखते हुए एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम गठित किये जाने को कहा गया है।

---

[6] सहायक आचार्य ई. ए. एफ. एम., स्व. राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाँदीकुई, दौसा, राजस्थान।

दुनिया भर में बचत और राजस्व के रूप में जमा खरबों डॉलर स्वाहा हो चुका है, वैश्विक जीडीपी में रोज कमी दर्ज की जा रही है, लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया है कि 90 देश उससे मदद मांग रहे है, आईएलओ के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में ढाई करोड़ नौकरियां खतरे में है, कोविड–19 के कारण चीन से होने वाले आयात के प्रभावित होने से स्थानीय और बाहरी आपूर्ति श्रृंखला के सन्दर्भ में चिन्ताऐं बढ़ी है।

बैकिंग के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

- **बैंक में जमा नगदी पर प्रभाव**

कोविड़ महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोगों की बैंक जमा और हाथ में रखी नगदी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। महामारी के कारण इलाज पर खर्च से लोगों का अच्छा–खासा पैसा निकला है। भारतीय रिजर्व बैंक की मासिक पत्रिका में अधिकारियों के एक लेख में यह कहा गया है। एक परिवार की कुल सम्पत्ति में बैंक जमा की हिस्सेदारी करीब 55% होती है। अप्रेल 2021 के अंत में इसमें 0.1% की गिरावट आई, जबकि अप्रेल 2020 में इसमें 1.1% की बढ़ोतरी हुई थी। बैंक कर्ज की तुलना में बैंक जमा में गिरावट की दर भी अधिक रही है।

बैंकों के लिए जोरदार मुनाफे के साथ सुरक्षित माने जाने वाले गोल्ड लोन अब मुसीबत बनते नजर आ रहे है। गोल्ड लोन में एनपीए तेजी से बढ़ रहा है। जून तिमाही में कुछ बैंकों का 83% एनपीए सिर्फ गोल्ड लोन की वजह से बढ़ा है। दरअसल आधे से ज्यादा गोल्ड लोन कोरोना की दस्तक के बाद बंटे है। उस समय सोने की कीमत 56 हजार रूपये प्रति 10 ग्राम थी। अब सोना 48 हजार रूपये के करीब है। ऐसे में बड़ी संख्या में कर्जधारक लोन चुकाने की जगह डिफॉल्ट करना अधिक फायदे का सौदा समझ रहे है। अप्रेल–जून तिमाही के लिए अब आए नतीजों के मुताबिक *ICICI* बैंक का एनपीए 7231 करोड़ रूपए बढ़ गया। इसमें 6773 करोड़ रिटेल लोन की हिस्सेदारी 1123 करोड़ रूपए रही। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस हेड प्रकाश अग्रवाल के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमत में आई गिरावट गोल्ड लोन के चलते बैंकों को हो रहे नुकसान की एक बड़ी वजह है।

बैंक क्रेडिट आर्थिक विकास की एक मुख्य घटक है। हालांकि पिछले दो सालों में बैंक क्रेडिट में गिरावट देखी गई। 2019–20 में बैंक ऋण वृद्धि दर 6.13% थी, जो 2020–21 में गिरकर 5.6% रह गई। महामारी के चलते वर्ष 2020–21 में बैंक क्रेडिट के स्वरूप में भी बदलाव आया है। आम तौर पर बैंक कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों को और व्यक्तिगत ऋण देते है। इस वर्ष सकल बैंक क्रेडिट में उक्त क्षेत्रों की हिस्सेदारी घटी है। महामारी से पहले कुल बैंक क्रेडिट में उद्योग जगत की हिस्सेदारी 32 से 33 प्रतिशत तक होती थी। उद्योगों में बैंक बड़े उद्योगों सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को ऋण देते हैं। 2020–21 में कुल बैंक ऋण में औद्योगिक ऋण की हिस्सेदारी घटकर 30 प्रतिशत से कम रह गई।

- **डिजिटल लेन देन में वृद्धि**

कोरोना काल के दौरान डिजिटल पेमेंट में इजाफा हुआ है। लोकप्रिय डिजिटल भुगतान मोड यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने नया रिकार्ड कायम किया है। इसके जरिए जून में 547373 करोड़ का लेनदेन हुआ है, जो अभी तक इसका उच्चतम स्तर है। नेशनल पेमेंटस कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के अनुसार, यूपीआई के जरिए हुए लेन–देन में मूल्य और मात्रा दोनों शर्तों में 10–11% का उछाल देखने को मिला है। इससे पहले यूपीआई ने मई के लिए 2.53 बिलियन लेन–देन देखे, जो मार्च 2021 के 2.73 बिलियन से कम थे। मूल्य के लिहाज से मई के लिए यूपीआई का लेन–देन 4.93 लाख करोड़ रूपये रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश के लोगों की सेहत के साथ आर्थिक स्थिति पर भी हमला किया गया है। स्कूल–कॉलेज बंद होने से कोई बेरोजगार हो गया तो किसी का लॉकडाउन के चलते रोजगार छिन गया। कई परिवारों की आर्थिक हालत पर कोरोना सहित अन्य बीमारियों ने जंजीरे डाल दी है। इस वजह से

पिछले साल के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान के लोगों ने सात हजार करोड़ रूपए ज्यादा लोन लिया है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जानकारों ने बताया कि लोन के जरिए युवाओं ने रोजगार हासिल करने की सबसे ज्यादा कोशिश की है।

- **कोविड़ काल के दौरान डिजिटल पेमेंट के साथ साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े**

हाल के वर्षों के दौरान देश के बैंकों में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढा है।, लेकिन साइबर फ्रॉड़ के मामले भी काफी तेजी से बढ़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकडों के मुताबिक देश में देश के सिटीजन साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड़ के मामले बीते 5 वर्षों मे 21 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए है। रकम के मामले में इस तरह के फ्रॉड़ करीब 300 फीसदी बढ़े है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान जहां बैंकों ने कार्ड, इंटरनेट धोखाधड़ी यानी एटीएम, डेबीट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधडी के 3223 मामले दर्ज किए थे। वहीं वित्त वर्ष 2020–21 में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 69410 हो गई। रकम के लिहाज से देखें तो जहां 2016–17 में कुल 45.56 करोड़ रूपए की धोखाधड़ी दर्ज की गई थी, वहीं 2020–21 में यह बढ़कर 200 करोड़ रूपए से भी अधिक हो गई। खास बात यह है कि बैंक ग्राहकों के साथ साइबर फ्रॉड की अधिकतर शिकायतें प्राइवेट बैंकों से जुड़ी हैं। बैंक ग्राहकों के साथ साइबर फ्रॉड के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए है। 2016–17 के दौरान महाराष्ट्र में ग्राहकों के साथ कार्ड, इंटरनेट से जुड़े बैंकिंग फ्रॉड के 1075 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2020–21 में बढ़कर 26522 हो गए।

- **देश में छोटे लोन की मांग**

देश में छोटे लोन की मांग बढ़ रही है। इस साल 30 जून तक की स्थिति के मुताबिक, घरेलू माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का लोन पोर्टफोलियों 4.2% बढ़कर2.37 लाख करोड़ रूपए तक पहुँच गया है। इसके मुकाबले 30 जून 2020 तक यह आंकड़ा 2.27 लाख करोड़ रूपए था। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस दौरान एमएफआई का एनपीए घटकर 4.73% रह गया जो 2018–19 में 5.19% था। केडिट रेटिंग एजेन्सी इन्फोमेरिक्स के मुताबिक ये छोटे–छोटे लोन 5.68 करोड़ लोगों ने लिए। 10.3 करोड़ लोन खातों में डाली गई कुल 2,37369 करोड़ रूपए की रकम में सबसे ज्यादा 1.02 लाख करोड़ की हिस्सेदारी बैंकों की रही। गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की इसमें 75.21 करोड़ की हिस्सेदारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक, एमएफआई का लोन पोर्टफोलियों बढ़ने का सीधा मतलब है कि छोटे पैमाने पर उद्योग–धन्धें बढ़ रहे है और लोग खर्च करने के लिए तैयार है, जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने का काम करती है। इन्फोमेरिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आगामी महीनों में छोटे लोन की मांग बढ़ेगी इसकी सबसे बड़ी वजह एनपीए में लगातार कमी है। इससे इंस्टीट्यूशंस के लिए फंड जुटाना आसान हो जाता है। अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने से डिमांड भी बढ़ने की संभावना है।

- **रिटेल सेक्टर की बिक्री में इजाफा**

देश की जीडीपी में 10% से अधिक और कुल रोजगार में 8% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले रिटेल सेक्टर की बिक्री का पिछले 2 महीनों से कोविड़ पूर्व स्तर से ज्यादा हो रही है। नवम्बर 2019 से 6% अधिक रही। वहीं 2020 की तुलना में यह बढ़ोतरी 16% अधिक है। हालांकि इस साल अक्टूबर की तुलना में रिटेल सेक्टर की बिक्री में लगभग 5% की गिरावट आई है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री नवम्बर में काफी अच्छी रही है, जो अक्टूबर में उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी। इसके अलावा देश में खेल गतिविधियां फिर से शुरू होने के बाद स्पोटर्स गुडस की बिक्री में भी 2019 के मुकाबले 18% ज्यादा रही है। देश के पश्चिमी हिस्से में रिटेल बिक्री सबसे अच्छी रही, जहां कोविड पूर्व स्तर से 11% और सालाना आधार पर 21% बढ़ात्तरी देखने को मिली। पूर्वी दक्षिणी भारत में रिटेल बिक्री कोविड पूर्व स्तर के 9% अधिक हुई है, जबकि सालाना आधार पर यह क्रमशः 20% और 11% अधिक है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के सीईओ कुमार राजगोपालन ने कहा कि देश में विजनेस में सुधार नजर आ रहा है और हमें उम्मीद है कि यह सुधार जारी रहेगा।

- **भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव**

कोविड–19 का प्रभाव किसी एक विशेष क्षेत्र पर ही नहीं पड़ा बल्कि यह भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई। अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्र और उनमें काम करने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित है जिसमें कृषि क्षेत्र प्रमुख है। देश का किसान इस समय कोविड–19 वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है, इससे पहले किसान प्राकृतिक आपदा जैसे कम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, तेज तूफान आदि आपदाओं से जूझ रहा था। ऐसे में लॉकडाउन (तालाबंदी) से देश के सब्जी, फल, फूल, दुध, मुर्गीपालक, पशुपालक, मधुमक्खीपालक किसान आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, कोरोना महामारी से इनकों उचित कीमत नहीं मिल रही है। जिससे प्रभावित होकर किसान आगे की खेती नहीं करना चाहता है। लॉकडाउन भारत में ऐसे समय शुरू हुआ जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार थी और खरीफ की फसल का काम शुरू हो गया था। देश के तमाम हिस्सों से खबरे आई की फूल, फल, सब्जियाँ खेत में सड़ने लगी, ग्रामीण क्षेत्रों में इनके इन्तजाम के लिए कोई भण्डारण व्यवस्था नहीं थी। बाजारों से जोड़ने वाली चैन खत्म हो गई। फल व सब्जियाँ खेत में सड़ गए। क्रेडिट सुईस की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को फल और सब्जियों के दाम गिरने व सड़ने के कारण लगभग 20 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। कोरोना महामारी के फैलने से फसलों की कीमतें कमजोर हो गई है, एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 6 वर्षों में धीमी गति से बढ़ रही है, मक्का, सोयाबीन, कपास और प्याज जैसी फसलों की कीमतें 50 फीसदी तक गिर गई है।

कोविड़ महामारी के बढ़ते प्रभाव के बीच शहरों की आबादी गाँव की तरफ वापस गई है, ऐसे समय में एक नई योजना के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान की परिकल्पना की जा सकती है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पादों के भण्डारण और क्रय–विक्रय केन्द्रों की व्यवस्था की जाए। यदि हम किसी भी एक लाभदायक व्यवसाय के रूप बदलने में कामयाब रहे तो एक बड़ी आबादी गांव में ही रूक जाएगी। इसेसे शहरों में जनसंख्या के घनत्व के रूप में बढ़ रहे एक संकट में कमी आएगी।

- **कृषि क्षेत्र के वितरण पर प्रभाव**

वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र ही एक ऐसी कड़ी है जो भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः सुचारू ढंग से चला सकती है देश में पहले से ही आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों को निरन्तर सरकारों की ओर से उपेक्षित किया गया है एन.एस.एस.ओ के अनुसार भारत के कुल कार्यबल का 90% हिस्सा असंगठित व्यवसाय में लगा हुआ है इसका मतलब है कि लोग किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित है ये ऐसे लोग किसी भी संकट की स्थिति में पहले से ज्यादा प्रभावित हुए है। सरकारों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आईएफडी के अध्यक्ष गिलबट एफ होंगबों ने 15 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के मौके पर कहा कि हमारे खाने के लिए अनाज उगाने वाली और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाली ग्रामीण महिलाएं महामारी के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महिलाओं की रक्षा के लिए अपने सामाजिक–आर्थिक प्रभावों पर कितना अधिक ध्यान देती है। ग्रामीण महिलाएं जो कि बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के अनौपचारिक तौर पर हासिल करती है। इस महामारी के दौरान पुरूषों के मुकाबले सबसे ज्यादा ग्रामीण महिलाएं बेरोजगारी का सामना कर रही है, होंगबों ने कहा कि ग्रामीण महिलाएं जिन लोगों पर अगली पीढ़ी को खिलाने और पालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनमें इस संकट के माध्यम से उपेक्षित किया गया है।

कोविड–19 का प्रभाव फसल सुरक्षा के लिए बीज, ट्रेक्टर, लेबर सहायता, दवाओं जैसे उत्पादों की अनुपलब्धता के कारण फसलों की बुवाई और कटाई में देरी है। सरकार को इन चीजों को उपलब्ध कराना चाहिए। सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों को समान प्राथमिकता देना बहुत महत्त्वपूर्ण है, यह क्षेत्र उपभोग की प्रवृत्ति और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार को गांव स्तर पर फसलों की खरीददारी की सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसानों के उत्पादों पर यातायात खर्च बचाया जा सके। वर्तमान परिदृश्य में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे ई–कॉमर्स खिलाड़ी गेमचेन्जर हो सकते है उनके पास किसानों का एक

टारगेस बेस है जो सीधे सरकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिससे समय के अन्तराल को कम किया जा सकता है। राज्य सरकारें तहसील स्तरों पर बारीकी से काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों की उपज को बाजार तक भेजने के लिए कृषि–इन्पुट मिल सके।

निष्कर्ष

भारतीय टिप्पणीकार रिजर्व बैंक से उम्मीद कर रहे है कि वह लचीली मौद्रिक नीतियां अपना कर आर्थिक गतिविधियों के प्रसार में योगदान करता रहे, दूसरी तिमाही में हुई 8.4% ग्रोथ संदेश दे रही है कि इससे अर्थव्यवस्था का आकार 4% तक बढ़ सकता है। महंगाई–बेरोजगारी पर नजर डालते ही साफ हो जाता है कि भारत को इस तरह के आर्थिक चिन्तन की कितनी जरूरत है। खुद सरकार के अनुसार शहरों में नियमित नौकरी करने वालों का अनुपात जनवरी से मार्च की तिमाही में 2020 के मुकाबले 2021 में घटकर 50.5 से 48. 1% रह गया है। आंकड़े यह भी बताते है कि अनियमित किस्म के रोजागर करने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है। यानी रोजगार की संरचना नियमित की जगह अनियमित की तरफ झुकती जा रही है। आठ महीने पहले के इन आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार का क्षेत्र महामारी के विपरीत प्रभाव से उबरने में नाकाम तो रहा ही है, साथ ही उसमें ऐसी नई विकृतियां पैदा हो गई हैं जिनका निराकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक उस पर विशेष ध्यान न दिया जाए। महंगाई के मामले में तो रणनीतिकारों को रवैया अजीब है। आंकड़ों की तिकढ़म से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लम्बे अरसे से 4.5% है। महंगाई बढ़ती रहती है, लेकिन यह सूचकांक स्थिर रहता है। उधर थोक मूल्य सूचकांक 12% से भी ज्यादा है। पिछले पूरे साल सरकार ने पेट्रोल–डीजल से खूब कमाई की। सरकारी प्रवक्ता कहते रहे यह हमारी इम्फार्ड चॉयस है। दलील यह है कि सोचे–समझे तरीके से तेल से पैसा कमाकर लोकोपकारी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव का मौसम आया, सरकार को यह इम्फार्ड चॉयस बदलनी पड़ी।

पिछले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। कोरोना की पहली लहर में कई लोगों की नौकरियां छूटी, आमदनी घटी, निवेश और बचत खत्म हो गई। पिछले वित्त वर्ष में गोल्ड ज्वैलरी के बदले लोन लेने में 82.3% उछाल आया। देश में सबसे बड़े बैंक एसबीआई के मुताबिक पारिवारिक कर्ज जीडीपी के 32.5% से बढ़कर 37.3% हो गया। केसल्टिंग फर्म ग्रांट थॉर्नटन के सर्वे के मुताबिक 40% व्हाइट कॉलर कर्मचारियों के वेतन में कटौती हुई। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटा–मोटा धंधा करके पेट पालने वालों की आमदनी भी लगभग 39% घट गई। अब सवाल यह है कि भारत की 7.8% की नार्मल ग्रोथ कब वापस लौटेगी। बढ़ती महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को भी मौद्रिक नीति को लेकर अपने मौजूदा रूख में बदलाव करना होगा। इसका मतलब यह होगा कि उन्हें सिस्टम में तरलता बढ़ाने के अपने–अपने प्रयासों से थोड़ा पीछे हटना होगा, ब्याज दरों में तेजी की तरफ जाना होगा।

कोविड–19 का प्रभाव किसी एक विशेष क्षेत्र पर ही नहीं पड़ा बल्कि लॉकडाउन में उन सभी उद्योगों की कमर तोड़ दी है। यह भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरे विश्व को ही प्रभावित किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है, अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्र और उसमें काम करने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित है जिसमें कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं वितरण पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है।

किसानों को इस महामारी के आर्थिक प्रभावों से बचाने के लिए त्वरित उपाय करने चाहिए जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। किसानों को सभी बाजारों को सीधे किसानों से उपभोक्ता व्यवस्था के रूप में समुदाय समर्थित कृषि एव सहकारी विपणन गतिविधियों को बिना किसी बाधा के काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, किसानों के फायदे के लिए गैर खाद्य फसलों को भी मुफ्त आवाजाही और बिक्री की अनुमति दी जाए। कृषि एवं लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगों को एक तिमाही के कर्ज पर ब्याज माफ किया जाना चाहिए तथा उन्हें अधिक रकम उपलब्ध कराना चाहिए, साथ ही फूलों, फलों, सब्जियों के उत्पादों के नष्ट होने से हुए नुकसान की भरपाई सरकारों द्वारा की जानी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. The Economic Times – 19.09.2020
2. MOHFW Govement of India
3. Covid-19; Impact on the Indian Economy, Indira Gandhi Institute of Development www.igidr.ac.in
4. बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थायें :– डॉ. स्वामी, गुप्ता
5. भारत की अर्थव्यवस्था :– डॉ. सी.पी.गुप्ता, वशिष्ठ शर्मा
6. प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिक विशेषांक भारतीय अर्थव्यवस्था–2021
7. दैनिक भास्कर 13 जून 2021
8. बिजनेस भास्कर 21 दिस. 2021
9. बिजनेस भास्कर 25.12.2021
10. राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति
11. इण्डिया टूडे, योजना, आऊटलुक

❖◆❖